भारत सरकार
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 91
सोमवार, 14 सितम्बर, 2020 को उत्तर के लिए नियत

विनिर्माण क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना

91. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2024 तक भारत को पाँच ट्रिलियन अमेरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के देश के लक्ष्य में विनिर्माण क्षेत्र को मुख्य क्षेत्र के तौर पर निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पूंजीगत वस्तु क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र का आधार है और सरकार ने वर्ष 2014 में पूंजीगत वस्तु क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता का संवर्धन करने के लिए एक योजना अधिसूचित की थी; और

(ग) यदि हां, तो आज की तारीख में वास्तविक और वितीय उपलब्धियों की दृष्टि से इस योजना की स्थिति और परिणामों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) से (ग): विनिर्माण क्षेत्र रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह श्रम गतिशीलता और मूल्य वर्धन के लिए कृषि तथा सेवा क्षेत्र के बीच मुख्य परिवर्तनीय सम्पर्क उपलब्ध कराता है।

कैपिटल गुड्स क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र की आधार है क्योंकि ये उन मशीनों का उत्पादन करता है जो मशीने बनाती हैं। यह क्षेत्र विनिर्माण उद्योगों के व्यापक सेट को महत्वपूर्ण मशीनरी और उपकरण उपलब्ध कराता है।

सरकार ने नवम्बर, 2014 में "भारतीय कैपिटल गुड्स क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता की वृद्धि" के लिए एक स्कीम को अधिसूचित किया। इस स्कीम से सरकारी सहायता के साथ होने वाले

प्रौद्योगिकी विकास के लिए शैक्षणिक जगत और उद्योग के बीच भागीदारी को प्रोत्साहन मिला। इस स्कीम के तहत ₹569.92 करोड़ की बजटीय सहायता की परियोजनाएं और ₹981.76 करोड़ का कुल परिव्यय मंजूर किया गया है। इनमें परीक्षण, प्रशिक्षण, प्रमाणन, साझा विनिर्माण और एमएसएमई के लिए टूल रूम सहित औद्योगिक समूहों को अवसंरचनात्मक और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए आईआईटीज, भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलुरू, सीएमटीआई बैंगलुरू, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन (एचईसी), रांची, एचएमटी, बैंगलुरू में स्थापित चार उद्योग 4.0 एसएएमएआरटीएच (समर्थ) केन्द्रों सहित 10 साझा इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्र (सीईएफसी) शामिल हैं।

आईआईटी मद्रास , आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईएससी, सीएमटीआई, पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नालॉजी में प्रौद्योगिकी विकास के लिए 8 उत्कृष्ठता केन्द्रों की स्थापना की गई है। उद्योग-शैक्षणिक जगत के सहयोग से मशीन टूल्स, वस्त्र मशीनरी, अर्थ मूविंग मशीनरी, नैनो एवं सेंसर प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में 25 नई स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का सफलता पूर्वक विकास किया गया है। इन प्रोटोटाइपों को वाणिज्यीकरण हेतु तैयार किया जा रहा है।

कर्नाटक सरकार की भागीदारी में तुमकुरू, कर्नाटक में एक 500 एकड़ के विश्वस्तरीय मशीन टूल पार्क की स्थापना की जा रही है। इस पार्क का उद्देश्य भारत में मशीन टूल्स उप-क्षेत्र की सामर्थ्य और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए उपलब्ध कौशल और विश्वस्तरीय अवसंरचना को बढ़ाना है।

स्कीम के प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि घटक के तहत पाँच विदेशी विनिर्माण प्रौद्योगिकियों की अधिप्रा की गई है। इनमें लम्बी लेथ मशीनों, वोल्टेज इलेक्ट्रिक केबलों, हाइड्रो टरबाइन की लेजर कलेडिंग और टिटेनियम शेल कास्टिंग प्रौद्योगिकी के लिए नई प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं।

स्कीम के तहत समर्थ उद्योग नामक एक पहल के माध्यम से भारतीय विनिर्माण यूनिटों द्वारा उद्योग 4.0 और स्मार्ट विनिर्माण के अंगीकरण को सुगम बनाने हेतु एक पारिस्थितिकी-तंत्र का सृजन किया गया है। आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बैंगलुरू, केन्द्रीय विनिर्माणकारी प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंगलुरू और किर्लोस्कर, पूणे के सहयोग से 4 समर्थ उद्योग केन्द्रों की स्थापना की गई है। ये प्रदर्शन केन्द्र सेमिनारों और वेबिनारों के माध्यम से समूचे औद्योगिक समूहों में स्मार्ट विनिर्माण के बारे में जागरूकता सृजन करने के अलावा पुरानी मशीनों का उन्नय करके, नैदानिक परीक्षण करके, कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करा कर स्मार्ट विनिर्माण प्रौद्योगिकियां अपनाने के लिए उद्योग की सहायता कर रहे हैं।

******